SHODH SAMAGAM

ISSN : 2581-6918 (Online), 2582-1792 (PRINT)

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना

आशीष दूबे, (Ph.D.), वाणिज्य विभाग
विवेकानंद महाविद्यालय, रायपुर, छत्तीसगढ़, भारत

ORIGINAL ARTICLE

Corresponding Author
आशीष दूबे, (Ph.D.), वाणिज्य विभाग
विवेकानंद महाविद्यालय, रायपुर, छत्तीसगढ़, भारत

shodhsamagam1@gmail.com

Received on : 01/01/2021
Revised on : -----
Accepted on : 08/01/2021
Plagiarism : 01% on 01/01/2021

शोध सार

भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है व विश्व की दूसरी बड़ी जनसंख्या वाला राष्ट्र है। श्रम संपन्नता के दृष्टिकोण से भारत समृद्ध राष्ट्र है। भारत की श्रम शक्ति का बड़ा भाग अकुशल है, तथा असंगठित क्षेत्रों में कार्यरत है, जो भारत में गरीबी का एक महत्वपूर्ण कारण है। प्राकृतिक संसाधनों से संपन्न एवं कृषि की संपन्नता के बाद भी भारत मे गरीबी का कारण कृषि पर अत्याधिक निर्भरता, आय एवं संपत्ति का असमान वितरण, विशाल उत्पादन का असंगठित क्षेत्र, शिक्षा, दीर्घकालीन गुलामी तथा परंपरागत अर्थव्यवस्था आदि शामिल है।

मुख्य शब्द

कृषि, गरीबी, अन्न योजना, कोविड–19.

स्वतंत्रता प्राप्ति के 73 वर्ष पूर्ण होने के बाद भी भारतीय अर्थव्यवस्था विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल रहा है, जिसका प्रमुख कारण दोषपूर्ण आर्थिक नियोजन, विदेशी ऋणों पर अधिक निर्भरता, नौकरशाही और भ्रष्टाचार रहा है।

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रगति का अध्ययन को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला उदारीकरण के पूर्व की स्थिति तथा दूसरा उदारीकरण के बाद की स्थिति। उदारीकरण के पूर्व की अर्थव्यवस्था परंपरागत भारतीय अर्थव्यवस्था एवं आर्थिक नियोजन का आधार घाटे पर आधारित बाजार की व्यवस्था थी। बजटीय घाटे की पूर्ति सरकार द्वारा ऋण लेकर अथवा अतिरिक्त मुद्रा का निर्गमन कर किया जाता रहा, जिसका प्रभाव भारतीय अर्थव्यवस्था पर अत्यंत नकारात्मक पड़ा। यही कारण था कि वर्ष 1991 में भारत में निजीकरण एवं उदारीकरण की नीति अपनाई गई। भारतीय नियोजन प्रक्रिया में असंगठित क्षेत्रों को नियंत्रित

करने के लिए कोई विशेष योजना नहीं बनाई गई, जो भारतीय अर्थव्यवस्था में गरीबी का अत्यंत महत्वपूर्ण कारण है। कोविड–19 की अवधि जो चीन के वुहान शहर से प्रारंभ होकर पूरे विश्व में फैल गया और इसका नकारात्मक प्रभाव पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। भारतीय अर्थव्यवस्था भी इस स्थिति से अछूता नहीं है। मार्च 2020 में भारत में कोरोना वायरस महामारी को रोकने के लिए देश के प्रधानमंत्री ने 24 मार्च को 21 दिनों के लिए पूरे देश में लागू करने का आदेश दिया। इसके बाद 14 अप्रैल को लॉक डाउन की अवधि को पुनः 3 मई तक बढ़ा दिया गया, और धीरे–धीरे देश में लॉक डाउन की अवधि को 30 जून तक बढ़ाया गया। लॉकडाउन बढ़ाने का प्रमुख कोरोना वायरस को नियंत्रित करना था, किंतु इस उद्देश्य पर आशातीत सफलता प्राप्त नहीं हुई। लॉक डाउन समाप्त किए जाने के बाद संक्रमण का खतरा और तेजी से बढ़ रहा है।

कोरोना का नकारात्मक प्रभाव देश के रोजगार क्षेत्रों पर पड़ा, विशेषकर असंगठित क्षेत्रों के में कार्यरत श्रमिक बेरोजगार हो गए। कोरोना वायरस के प्रभाव से लॉकडाउन एवं बाजार में अस्थिरता रही, जिसके कारण तेजी से बेरोजगारी बढ़ी तथा आपूर्ति संख्याओं पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। सरकार की आय में कमी आई, पर्यटन उद्योग का पतन हुआ, उपभोक्ता गतिविधियों में कमी आई, होटल उद्योग का पतन हुआ, ईंधन में खपत में गिरावट आई। भारत में 2020 में कोरोना वायरस महामारी का आर्थिक प्रभाव काफी हद तक विघटनकारी रहा। सांख्यिकी मंत्रालय के अनुसार वित्त वर्ष 2020 की चौथी तिमाही में भारत की वृद्धि दर घटकर 3.1 प्रतिशत रह गई। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का अनुमान है कि भारतीय अर्थव्यवस्था 4.5 प्रतिशत की दर से सिकुड जाएगी।

उपरोक्त तथ्य कोरोना काल में भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव को प्रदर्शित करते है, और कोरोना काल की अवधि जितनी लंबी होगी भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए यह स्थिति और भी अधिक घातक होगी। रोजगार की कमी का एवं लॉकडाउन उनका गरीब मजदूर परिवारों पर अत्यंत नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। अतः गरीब परिवारों को राहत देने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की घोषणा की गई। 26 मार्च 2020 को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री गरीब उत्सव अन्न योजना की घोषणा वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण के द्वारा किया गया। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में गरीबों के लिए विभिन्न योजनाएं शामिल है। उन्ही योजनाओं में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना भी एक है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत सरकार ने देश के 80 करोड़ से अधिक राशन कार्ड धारकों को अप्रैल मई और जून माह के लिए राशन कार्ड में दर्ज सदस्यों के आधार पर प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज (गेहूं अथवा चावल) प्रति परिवार 1 किलो दाल मुफ्त देने की घोषणा भी की है। यह मुफ्त 5 किलो अनाज राशन कार्ड पर मिलने वाले अनाज के वर्तमान कोटे के अतिरिक्त है। जून के अंतिम सप्ताह में प्रधानमंत्री जी ने इस योजना का विस्तार दिवाली और छठ के पूजा तक कर दिया है। 30 जून को राष्ट्र के नाम के संदेश में प्रधानमंत्री जी ने ऐलान किया कि देश के गरीब परिवारों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत दिए जाने वाले मुफ्त अनाज नवंबर तक दिए जाएंगे।

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के विस्तार पर 90000 करोड़ से ज्यादा खर्च होंगे, इसके साथ ही इस योजना में कुल व्यय लगभग 1.50 लाख करोड़ रुपए हो जाएगा। इस योजना के विस्तार के बाद राशन कार्ड धारकों को सदस्य संख्या के आधार पर प्रति सदस्य 5 किलो अनाज (गेहूं या चावल) तथा 1 किलो चना दाल प्रति परिवार को मुफ्त दिया जाएगा। कोरोना काल में गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत संचालित योजना उन परिवारों के लिए अत्याधिक लाभदायक है, जो गरीब है, तथा कोरोना के कारण जिनके आय तथा रोजगार पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है।

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का संचालन प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत किया गया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना केंद्र सरकार की एक योजना है, जिसके अंतर्गत अघोषित संपत्ति की राशि व्यक्ति द्वारा बैंक में जमा कराया जाएगा तथा सरकार द्वारा इस राशि का उपयोग गरीबों के कल्याण के लिए किया जाएगा। सरकार द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत अनेक कार्यक्रमों का संचालन किया जा रहा है।

जिसके अंतर्गत जरूरतमंदों को नगद रूप में प्रत्यक्ष राशि का हस्तांतरण, मुफ्त घरेलू सिलेंडर प्रदान करना, मुफ्त अनाज वितरण एवं अन्य विभिन्न आवश्यकताओं के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराया जाता है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का प्रारंभ दिसंबर 2016 को किया गया। इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी को प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता के लिए बैंक में खाता खुलवाना निश्चित किया गया, जिससे हितग्राही को प्रत्यक्ष रूप से निर्धारित सहायता प्राप्त हो एवं योजना में पारदर्शिता भी बनी रहे। गरीबों के कल्याण में यह योजना प्रभावशाली रही तथा देश के करोड़ों गरीबों को इस योजना से प्रत्यक्ष रूप से आर्थिक लाभ प्राप्त हुआ है।

कोविड–19 के अवधि में जो पूरे मानवीय सभ्यता के लिए चुनौती है। इस अवधि में यह योजना देश में गरीबों के कल्याण के लिए अत्यंत लाभदायक है। किसी भी मनुष्य के जीवन भी प्रमुख तीन आधारभूत आवश्यकताएं है, रोटी कपड़ा और मकान। जिसमें रोटी भी आवश्यकता सर्वोपरि है। कोविड–19 के प्रभाव से जहां रोजगारों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है, वहां प्रधानमंत्री गरीब अन्न योजना गरीबों की रोटी की आवश्यकता की पूर्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इस योजना के अंतर्गत अनाजों का वितरण राज्य के (पी.डी.एस.) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से राज्य के राशन दुकानों के द्वारा किया जा रहा है, और सुलभता से लाभार्थी तक पहुंचाया जा रहा है जो इस योजना की सफलता का आधार है।

इस योजना के अंतर्गत देश के 80 करोड़ से अधिक नागरिक लाभ प्राप्त कर रहे है। अतः यह कहा जा सकता है कि कोविड–19 के चुनौतीपूर्ण समय में सरकार की यह योजना गरीबों के लिए लाभदायक है। देश के गरीबी के कारणों में आय का असमान वितरण भी शामिल है। सरकार की प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना गरीबों को प्रत्यक्ष रूप से आर्थिक लाभ पहुंचा कर कुछ हद तक गरीबों की आर्थिक स्थिति को सम्हालने में सफल रहा है।

वैश्विक आर्थिक परिदृश्यों में गतिशीलता सदैव बनी रहती है और अमीरी तथा गरीबी का संघर्ष हर अर्थव्यवस्था की मूलभूत विशेषता होती है। इतिहास के अध्ययन से यह स्पष्ट है कि किसी भी काल में इस अमीर तथा गरीबी के संघर्ष को समाप्त नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यह मानवीय प्रवृति होती है, कि वह सदैव अपने को श्रेष्ठ साबित करना चाहता है, जिसके लिए जीवन के हर स्तर पर अलग–अलग पैमाना होता है। बाल्यकाल में बालक सदैव लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए अलग–अलग भाव भंगिमा तथा शैतानियां करता है और अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने का प्रयास करता है और जब वह शिक्षा ग्रहण करना प्रारंभ करता है, तो श्रेष्ठता साबित करने का आधार विषय में पकड़ परीक्षा के अंक आदि हो जाते है, और इस संघर्ष का अंतिम चरण अमीरी और गरीबी का होता है, जो जीवन पर्यन्त चलता रहता है। ऐतिहासिक तथ्यों से स्पष्ट हो चुका है कि अनेक संघर्षों के कारण यही अमीरी गरीबी की लड़ाइयाँ है। गरीबों के बढ़ते हुए असंतोष को नियंत्रित करना आवश्यक है, अन्यथा यह संघर्ष विध्वंशक हो जाता है। एक व्यक्ति के लिए भूख की समस्या सबसे बड़ी समस्या होती है और भूखा व्यक्ति पूर्णतः अनियंत्रित होता है, और वह कुछ भी कर सकता है। मानवता के दृष्टिकोण से भी कोई भूखा रहे या उचित नहीं है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना दिसंबर 2016 को प्रारंभ की गई जिसका उद्देश्य भारतीय अर्थव्यवस्था में गरीबी दूर करना और गरीबों को उपयुक्त सुविधाएं उपलब्ध कराना था। वही कोविड–19 की चुनौतीपूर्ण अवधि में इस योजना का विस्तार प्रधानमंत्री कल्याण अन्न योजना के प्रारूप में किया जाना एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक कदम है, जो भारतीय शासन व्यवस्था के कल्याणकारी स्वरूप को प्रदर्शित कर रहा है। वर्तमान परिस्थितियों में रोजगार के संदर्भ में चुनौतियां लगातार बढ़ रही है, क्योंकि अब तक कोरोना पर नियंत्रण के लिए प्रभावशाली विधि नहीं बनाई जा सकी है। कोरोना–19 का नकारात्मक प्रभाव विश्व के समस्त अर्थव्यवस्थाओं पर पड़ रहा है, किंतु भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए यह चुनौती और भी बड़ी हो गई है, जिसका प्रमुख कारण विशाल जनसंख्या तथा अर्थव्यवस्था का समाजवादी स्वरूप है। देश भी प्रजातंत्र व्यवस्था देश के प्रशासन तथा सरकार की जवाबदारी बढ़ा देती है। अन्न वितरण की योजना कोरोना काल में अत्यंत कल्याणकारी योजना है। विशाल भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए योजना प्रभावशाली वितरण व्यवस्था के कारण सफल रही है। वर्तमान परिस्थितियों में यह कह पाना कठिन है कि कोरोना कब तक नियंत्रित हो पाएगा और नवंबर तक ही इस योजना की आवश्यकता होगी। इस बात की संभावना है कि कोरोना की चुनौतीपूर्ण स्थितियां भविष्य में भी जारी रहे। ज्यों–ज्यों यह कोरोना काल

बढ़ता जा रहा है, यह अर्थव्यवस्था के लिए घातक हो रहा है, और इसका प्रभाव संपूर्ण वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाला है। पिछले तिमाही में भारतीय सर्वेक्षण संसाधन द्वारा जारी आंकड़ों के आधार पर देश की आर्थिक विकास दर घटकर 3.1 रह गई है, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का अनुमान है इस वित्तीय वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था 4.5 प्रतिशत की दर से सिकुड़ जाएगी, अर्थात् देश में रोजगार के अवसरों की कमी आएगी और देश में गरीबी बढ़ेगी।

सरकार द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से रियायती दरों पर चावल (रुपए 2 किलो) गेहूं (रुपए 3 किलो) की दर पर राशन कार्ड में दर्ज सदस्य संख्या के आधार पर उपलब्ध किया जा रहा है। लेकिन बेरोजगारी के कारण बड़ी मात्रा में ऐसी जनता भी है जो इस भुगतान के लिए सक्षम नहीं है, वे आवश्यकताओं को पूर्ण नहीं कर पाते है। इन परिस्थितियों में मुफ्त अन्न योजना ऐसे लोगों के लिए बड़ा सहारा है। यदि कोरोना काल की अवधि में और अधिक वृद्धि होती है, तो सरकार के लिए यह आवश्यक होगा कि इस योजना का पुनः विस्तार किया जाए, लेकिन आगामी विस्तार के पूर्व इस योजना की पुनः समीक्षा एवं सुधार किया जाना आवश्यक है। ऐसी अनेक विसंगतियां सामने आई है, जैसे लाभार्थी को समय–समय पर अनाज प्राप्त नहीं हो पाया या ऐसे लोग ने इस योजना का लाभ उठाया जो दायरे में नहीं थे। अतः आवश्यक है कि यदि इस योजना का भविष्य में विस्तार किया जाता है, तो पुनः योजना की समीक्षा किया जाए, साथ ही साथ इस तरह से नियोजन किया जाए, जिससे यह योजना मनरेगा की तरह प्रत्यक्ष रूप से रोजगार से जुड़ जाए, इस तरह के नियोजन से इस योजना की महत्ता और अधिक बढ़ जाएगी।

निष्कर्ष

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना देश में गरीबों के लिए अत्यंत कल्याणकारी योजना है, और कोरोना काल में इस योजना का विस्तार इस योजना का विस्तार प्रधानमंत्री गरीब योजना के रूप में किया जाना कोरोना काल में जन सामान्य के लिए लाभदायक है। यह एक महत्वकांक्षी योजना है, जिसका विस्तार भविष्य में कोरोना काल के बाद भी किया जाना देश के लिए लाभदायक होगा। इस योजना को और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए विधि स्थानीय स्तर पर जरूरतमंदों के लिए प्रतिनिधियों को शामिल कर और उन्हें इस योजना के क्रियान्वयन में शामिल कर और अधिक प्रभावशाली बनाया जा सकता है। स्थानीय स्तर पर प्राप्त सुझावों को भी इस योजना मे शामिल कर और अधिक प्रभावशाली बनाया जा सकता है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना कोरोना काल में भारतीय गरीबों विशेषकर प्रवासी मजदूरों, दैनिक कामगारों, स्थाई रोजगार में संलग्न जनसाधारण के लिए लाभदायक रहा है। इस योजना को केवल कोरोना काल तक सीमित रखना उचित नहीं होगा। आवश्यक है कि इस योजना के पूर्व अनुभवो के आधार पर उचित नियोजन कर भारतीय गरीब जिन्हें आवश्यकता है, अन्न उपलब्ध कराया जाए ताकि हमारे देश का कोई नागरिक भूखा ना रहे ।

संदर्भ सूची

1. nios.ac.in/media/documents/333H/qp.pdf
2. secure.evidhan.nic.in/SecureFileStructure/AssemblyFiles/13/9/20200302/Documents/3_1.pdf
3. issuu.com/saded.com.in/docs/bhukh_ka_asali_chehara__edited_
4. irfc.nic.in/wp-content/uploads/2019/06/Annual-Report-Hindi-2013-2014.pdf
5. urban.rajasthan.gov.in/content/dam/raj/udh/lsgs/lsg-jaipur/pdf/stp%20cell/rajasthan-land-allotment-policy.pdf

****